BEFORE THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL AT DEHRADUN

Present: Hon'ble Mr. D.K. Kotia

------- Vice Chairman (A)

CLAIM PETITION NO. 24/SB/2016

Dinesh Rana S/o Sri Bulak Singh Rana, Presently posted as Head Constable 10 (CP) in Police Station, District Pauri Garhwal, Uttarakhand.

……Petitioner

VERSUS

1. State of Uttarakhand through Secretary, Department of Home, Govt. of Uttarakhand, Secretariat, Dehradun.
2. Inspector General of Police, Garhwal Range, Dehradun.
3. Superintendent of Police, Pauri Garhwal.

.....Respondents

Present: Sri Jugal Tiwari, Ld. Counsel, for the petitioner

Sri U.C.Dhaundiyal, Ld. A.P.O. for the respondents

JUDGMENT

DATE: August 28, 2017

1. The petitioner has filed the claim petition for seeking the following relief:

"(i) The impugned order dated November 08, 2013 of the Superintendent of Police Pauri awarding the punishment of censure may kindly be set aside.

(ii) The appellate order dated 24 October 2015 of the Inspector General of Police Garhwal Range may also be set aside.

(iii) The impugned order of the S.P., Pauri may be removed from the Character Roll of the petitioner so that it may not mar his future career.

(iv) Issue any other order or direction which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the circumstances of this case."

2. The petitioner is a head constable in civil police in the Uttarakhand Police. The petitioner was issued a show cause notice dated 03.10.2013 by the Superintendent of Police, Pauri as to why the censure entry be not given to him as a minor penalty under "The Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991". The said Rules hereinafter have been referred to as "Rules of 1991". The allegation against the petitioner, based on the preliminary inquiry, in the show cause notice reads as under:-

"कारण बताओ नोटिस

हे0कानि0 10 ना0पु0 दिनेश राणा
द्वारा प्रतिसार निरीक्षक, पौड़ी।

वर्ष – 2013 में जब आप थाना धुमाकोट में हेड मोहर्रिर के पद पर नियुक्त थे तो दिनांक 08.09.2013 को थाना हवालात में निरूद्ध नामजद अभियुक्त अजय पाल सिंह मु0अ0सं0–07/2013 धारा 307 भादवि को कानि. निगरानी 477 ना0पु0 दीपेन्द्र कुमार द्वारा खाना खिलाने के लिए थाना के भोजनालय में ले जाया गया तथा वापस हवालात लाते समय उसकी अभिरक्षा से फरार हो गया। थाना हवालात में निरूद्ध अभियुक्तों को खाना मैस से लाकर हवालात में ही खिलाया जाता है। थाना हवालात की चाबी हेड मोहर्रिर की सुपुर्द में रहती है आपके थाना पर मौजूद रहते हुये कान्स0 निगरानी द्वारा अभियुक्त को हवालात से निकालकर खाना खिलाने के लिए मैस में लेकर जाना तद्पश्चात् अभियुक्त का कान्स0 की अभिरक्षा से फरार होना आपका अपने कर्तव्य में प्रति शिथिलता एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है, यदि आपके द्वारा हवालात की चाबी अपनी सुपुर्दगी में रखी होती और कान्स0 निगरानी को अभियुक्त को खाना हवालात में खिलाने हेतु निर्देशित किया गया होता तो अभियुक्त के अभिरक्षा से फरार होने की घटना को रोका जा सकता था। थाना हेड मोहर्रिर

के पद पर नियुक्त रहते हुए आपका यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है।

उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक पौड़ी श्री जी0आर0 वर्मा से प्रारम्भिक जांच कराई गयी। पुलिस उपाधीक्षक पौड़ी ने अपनी जांच आख्या दिनांक 27.09.2013 में आपको अभियुक्त अजय पाल सिंह के पुलिस अभिरक्षा से भाग जाने एवं अपने कर्तव्य प्रति लापरवाही बरतने का पूर्णत दोषी पाया गया है। फलस्वरूप आपके उक्त कृत्य के लिये आपके विरूद्ध उत्तराखण्ड (उ0प्र0) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली –1991 (अनुकूलन एवं उपरान्तरण) आदेश –2002 के नियम 4(1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (चार) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर आपके उपरोक्त कृत्य हेतु क्यों न आपकी चरित्र पंजिका में निम्न प्रकार से परिनिन्दा लेख अंकित कर दिया जाये , का कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाता हैः–

'' 2013''

वर्ष –2013 में जब यह हे0कान्स0 थाना धुमाकोट में हेड मोहर्रिर के पद पर नियुक्त था तो दिनांक 08.09.2013 को थाना हवालात में निरूद्ध नामजद अभियुक्त अजय पाल सिंह सम्बन्धित मु0आ0सं0– 07/2013 धारा 307 भादवि को कानि0 निगरानी 477 ना0पु0 दीपेन्द्र कुमार के द्वारा खाना खिलाने के लिए थाना के भोजनालय में ले जाया गया था तथा वापस हवालात लाते समय उसकी अभिरक्षा से फरार हो गया। थाना हवालात में निरूद्ध अभियुक्तों को खाना मैस से लाकर हवालात में ही खिलाये जाने का नियम है। थाना हवालात की चाबी हेड मोहर्रिर के सुपुर्द रहती है इस हेड मोहर्रिर के थाना पर मौजूद रहते हुये कान्स0 निगरानी द्वारा अभियुक्त को हवालात से निकालकर खाना खिलाने के लिए मैस में लेकर जाना तद्पश्चात् अभियुक्त का कान्स0 की अभिरक्षा से फरार होना हेड मोहर्रिर को अपने कर्तव्य में प्रति शिथिलता एवं घोर उदासीनता को प्रदर्शित करता है, यदि इस हेड मोहर्रिर के द्वारा हवालात की चाबी अपनी सुपुर्दगी में रखी होती और कान्स निगरानी को अभियुक्त को खाना हवालात में खिलाने हेतु निर्देशित किया गया होता तो अभियुक्त के अभिरक्षा से फरार होने की घटना को रोका जा सकता था। थाना मोहर्रिर के पद पर नियुक्त रहते हुए हे0का0 का यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है, जसकी घोर परिनिन्दा की जाती है।

अतः आप इस कारण बताओं नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आपको उपरोक्त सम्बन्ध में क्या कहना है। आपको यह स्पष्ट किया जाता है कि नियत अवधि के अन्दर आपका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उस सहानुभूतिपूर्व विचार करने के पश्चात् ही अग्रिम आदेश पारित किये जायेंगे, यदि आपका स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो आपके स्पष्टीरकण के अभाव में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये जायेंगे, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रकरण से सम्बन्धित जांच आख्या भी संलग्न की जा रही है।

संलग्नः जांच आख्या
पत्रांक :–द–32 /2013 पुलिस अधीक्षक
दिनांक –अक्टूबर 03, 2013
पौड़ी गढ़वाल ।"

3. The petitioner submitted the reply to the show cause notice on 30.10.2013 and denied the charge levelled against him. Superintendent of Police, Pauri considered the reply to show cause notice and did not find the same satisfactory and he found the petitioner guilty and awarded minor punishment of censure entry on 08.11.2013. The petitioner filed an appeal against the punishment order which was rejected by the Inspector General of Police, Garhwal region on 24.10.2015. Hence, the petition.

4.1 The petitioner has contended in the claim petition that the alleged incident occurred in the absence of the petitioner and for absconding the accused Ajay Pal Singh from lock-up of the police station, there was no negligence or carelessness on the part of the petitioner. The petitioner has specifically referred to para 2 of his reply to the show cause notice which reads as under:

> "2:– यह कि स्पष्टीकरण के अन्य तर्क प्रस्तुत करने से पूर्व इस प्रकरण के उन संगत एवं सम्बन्धित तथ्यों को कालक्रमनुसार उल्लेख निम्नवत किया जा रहा है, जिससे प्रार्थी निर्दोष सिद्ध होता है तथा जिनपर इस स्पष्टीकरण के न्यायिक उचित एवं विवकेपूर्ण निस्तारण के लिए मान्यवर द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है:–
>
> माह सितम्बर 2013 को मैं कार्यवाहक हेड मोहिर्रिर थाना धूमाकोट नियुक्त था, क्योंकि प्रधान लेखकर जे0पी सती बाहर डियूटी में रूद्रप्रयाग गये हुए थे। दिनांक 08–9–2013 को दोपहर करीब 13:00 बजे मेरे द्वारा कां0 क्लर्क 352 ना0पु0 दिनेश सिंह को मालखाने की चाबी व कार्यभार आदि सौंपकर यह बताया गया कि मुझे कल प्रातः पुलिस लाईन पौड़ी में सीसीटीएनएस कोर्स में जाना है जिसका आदेश संदेश प्रपत्र पर नोट है, तथा यह कहकर कि मेरी रवानगी 16:00 बजे करीब कर देना, मै वाया दुगडडा होकर पौड़ी जाउंगा उसके बाद मैं अपनी मोटस साईकिल से थाने से निकल पड़ा। हल्दूखाल के करीब पहुंचने पर मुझे याद आया कि मैने एक कार्ड धूमाकोट में प्रिटिंग प्रेस में रखा है जोकि वहीं छूट गया है जिस कार्ड की मुझे पौड़ी में आवश्यकता थी, इसलिए मजबूरन मुझे वापस धूमाकोट बाजार लौटना पड़ा। चूंकि मैं जानता था कि S.O. साहब भी सरकारी गाड़ी से पौड़ी जायेगें इसलिए मैने भी सुबह एस0ओ0 साहब के साथ जाने का निर्णय लिया। सांय करीब 6:40 बजे थाने की गाड़ी बाजार की तरफ आयी तब एस0ओ0 साहब ने बताया कि गाड़ी में मुल्जिम है जिसे थाने ले जा रहे हैं। मैने एस0ओ0 साहब को

बताया कि मै कल सुबह आपके साथ पौड़ी आउंगा। इसके बाद एस0ओ0 साहब थाने की तरफ चले गये और मैं कुछ समय बाजार में ही रहा। रात्रि करीब 7:50 बजे मै थाने पर पहुंचा, मैने कां0 क्लर्क दिनेश सिंह से मालूमात की तो उसने बताया कि मुल्जिम को डाक्टरी कराने के बाद हवालात में दाखिल कर दिया है तथा निगरानी डियूटी पर कां0 477 ना0पु0 दीपेन्द्र को नियुक्त किया गया है। मैने एस0ओ0 साहब से सुबह चलने के बारे पूछा तो उन्होंने बताया कि सुबह 4:00 बजे पौड़ी के लिए निकलेंगे, इसके बाद मै कानि0 क्लर्क 353 ना0पु0 दिनेश सिंह को आवश्यक दिशा–निर्देश देकर ऊपर अपनी बैरक में चला गया। स्पष्ट है कि अभियुक्त अजयपाल को थानाध्यक्ष महोदय ने मेरी अनुपस्थिति में थाने पर दाखिल किया और जी0डी0 में प्रविष्टि कराई जो कानि0 क्लर्क दिनेश सिंह द्वारा की गयी। इसलिए अभियुक्त की निगरानी व हवालात की चाबी प्रार्थी के पास होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

रात्रि करीब नौ बजे मुझे हो हल्ला सुनाई दिया, मै तुरन्त बाहर आया तो चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि मुल्जिम भाग गया है, पकड़ो पकड़ो तथा सभी कर्मचारी गण थाना गेट के बाहर की ओर भागे इस घटना की जानकारी मेरे द्वारा का0 133 ना0 पु0 अरशद व एस0ओ0 साहब को फोन से दी गयी।

श्री खजान सिंह चौहान थानाध्यक्ष उस समय बाजार में थे तथा फोन से सूचना मिलने पर उन्होंने थाने आकर एन0सी0आर0 धारा 217/223 भा0द0वि0 दिनांक 08–9–2013 को धूमाकोट पर अंकित करा दी तथा उस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं।

उल्लेखनीय है कि थानाध्यक्ष महोदय की एन0सी0आर0 में मेरे विरूद्ध वह आरोप नहीं लगाये गये जो आरोप कारण बताओ नोटिस में लगाये गये हैं क्योंकि वास्तव में अभियुक्त को मेरे द्वारा हवालात में बन्द नहीं कराया गया था बल्कि कानि0 क्लर्क दिनेश कुमार ने दाखिल किया था इसकी प्रविष्टि जी0डी0 रपट न0 30 व 29 समय 19:45 व 18:50 बजे दिनांक 08–9–2013 पर की भी की गयी था जिसकी छाया प्रति कानि0 क्लर्क दिनेश कुमार व थानाध्यक्ष महोदय ने ही जी0डी0 में प्रविष्टि करने के बाद अभियुक्त अजयपाल को हवालात में बंद करके कानि0 477 दीपेन्द्र की निगरानी में दिया था तथा प्रार्थी वहां पर मौजूद भी नहीं था और जब कानि0 दीपेन्द्र अभियुक्त अजयपाल को हवालात से मैस खाना खिलाने के लिए ले गया और वापसी में अभियुक्त उसकी हिरासत से भाग गया तब भी प्रार्थी थाना कार्यालय में मौजूद नहीं था और जैसा ऊपर अंकित किया जा चुका है कि अभियुक्त अजयपाल की कानि0 दीपेन्द्र की हिरासत से भागने की सूचना फोन से थानाध्यक्ष साहब को दी थी जोकि बाजार में थे।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी वास्तव में निर्दोष है और करण बताओ नोटिस में प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कथित आरोप लगाना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है।''

4.2 The petitioner has also contended that the preliminary inquiry was conducted in a casual manner; the findings of the preliminary inquiry are based on conjectures and surmises and not on the solid proof; the disciplinary authority did not consider his reply to the show cause notice properly and he passed the punishment order summarily, cursorily and mechanically without application of mind; the punishment order and appellate order both are non-speaking and unreasoned order; and since a criminal case was also initiated on identical facts and evidence, the departmental proceedings should have been stayed till the conclusion of the criminal case.

5.1 The claim petition has been opposed by respondents No. 1 to 3 and it has been contended in their joint written statement that when the petitioner was present at the police station, one accused namely Ajal Pal Singh who was in lock-up in the custody of the police, taken out from lock-up to the dining hall for food in the night of 08.09.2013 and while bring him back to the lock-up after food, the accused ran away from the police station. The allegation against the petitioner is that the key of lock-up is kept by the head moharrir (the petitioner); the food to any accused in custody is served in the lock-up and he is not taken to the dining hall; and the petitioner was present in the police station when the incident took place. Due to negligence and carelessness of the petitioner, the accused in custody ran away. Had the petitioner kept the key of the lock-up with him and the accused was not allowed to have food outside the lock-up, the incident of running away of the accused could have been avoided. The Deputy Superintendent of Police, Pauri was appointed to conduct the preliminary inquiry. During the course of the inquiry, the inquiry officer recorded the

statement of the petitioner, the incharge of the police station and 8 other police personnel who were on duty on the date of incident. The inquiry officer after conducting the inquiry reached the conclusion that the petitioner along with others was guilty and due to negligence and carelessness of the petitioner, the accused in custody had run away. The analysis and conclusion of the inquiry by the inquiry officer reads as made (Annexure: A8):-

"जांच विश्लेषण– जांच विश्लेषण से पाया कि दिनांक 8–9–2013 को थाना धुमाकोट के मु0अ0सं0–7/2013 धारा 307 भादवि0 में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अजयपाल पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी भरतपुर थाना धुमाकोट को थाना हवालात में निरूद्ध, जो कानि0 निगरानी 477 ना0पु0 दिपेन्द्र सिंह द्वारा खाना खिलाने के लिए थाने के भोजनालय में ले गया तथा वापस हवालात ले जाते समय अभिरक्षा से भाग जाने के सम्बन्ध में थाना धुमाकोट के अधि0/ कर्म0 के बयान अभिलिखित किये गये, जिसमें थानाध्यक्ष खजान सिंह चौहान द्वारा अपने बयानों में हवालात की चाबी हेड मोहर्रिर दिनेश राणा के पास होना बताया गया, कानि0 477 ना0पु0 दिपेन्द्र सिंह व उसके सहायक के रूप में कानि0 489 ना0पु0 सतीश कुमार को व सभी कर्म0 को उचित निर्देश देकर बाजार में खाना खाने हेतु जाना बताया गया तथा कर्मचारियों को उक्त संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश का उल्लेख रपट नं0 32 पर अंकित किया गया है, किन्तु कानि0 489 नापु0 सतीश कुमार को निगरानी ड्यूटी बताये जाने के संबंध में कोई उल्लेख रो0आम में नहीं, किया गया।

हे0मो0 10 ना0पु0 दिनेश राणा द्वारा पौड़ी प्रशिक्षण में जाने हेतु दिनांक 08.09.2013 सांय 4.00 बजे रवानगी करने के लिये कानि0 क्लर्क 352 नापु0 दिनेश सिंह को बताया गया तर्कसंगत नहीं है, और यदि वह आधे रास्ते से थाने पर वापस आ गये थे जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अभियुक्त को हिरासत से भाग जाने की सूचना उनके द्वारा कानि0 133 नापु0 अरशद को दी थी, जिससे स्पष्ट होता है कि तत समय हे0मो0 10 ना0पु0 दिनेश राणा थाने पर मौजुद था व अपने कर्तव्यों के पालन करने से वह विमुख नही हो सकता। कानि0 477 नापु0 दिपेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त को भोजनालय में खाना खिलाने के लिये ले जाया गया किन्तु हवालात की चाबी उसको किसने दी थी तथा यदि चाबी उसी के पास थी तो उसको किसने दी थी, कानि0 क्लर्क 352 नापु0 दिनेश सिंह द्वारा थाना कार्यालय में मौजुद रहते हुये भी घटना की जानकारी से अनभिज्ञता जताना और कार्य करने में व्यस्त कहने का कथन भी प्रश्न उठाता है। कानि0 सतीश कुमार को निगरानी ड्यूटी बताये जाने का भी रो0आम/ड्यूटी रजिस्टर में अंकन नही किया गया है। यदि कानि0 489 नापु0 सतीश कुमार को निगरानी ड्यूटी थानाध्यक्ष द्वारा बतायी गयी थी तो उसके द्वारा पालन क्यों नहीं किया गया, तथा अभियुक्त द्वारा भी अपने को मैस में खाना खिलाते समय एक ही सिपाही को साथ होना बताया गया जिससे प्रश्न खड़ा होता है कि अभियुक्त को खाना खिलाने के लिये एक ही कानि0 गया हो, सभी कर्मचारियों द्वारा अभिलिखित कराये गये बयानों में भी विरोधाभास उत्पन्न

हो रहा है। उपरोक्त बातों से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि थानाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अपने कर्तव्यों के पालन करने में शिथिलता बरती गयी, ऐसा प्रतीत होता है। यदि उनके द्वारा इस संबंध में थाने मे मौजूद रहकर उचित नियन्त्रण किया जाता तो यह घटना घटित नहीं होती।

अभि0 को हवालात से बाहर निकालकर खाना खिलाने का पुलिस रेगुलेशन में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जबकि मैस से खाना लाकर अभि0 को हवालात में ही खिलाया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा नही किया गया, यदि हेड मोहर्रिर 10 ना0पु0 दिनेश राणा, कानि0 क्लर्क 352 ना0पु0 दिनेश सिंह, निगरानी पर कानि0 477 ना0पु0 दिपेन्द्र सिंह व कानि0 489 ना0पु0 सतीश कुमार द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सतकर्ता बरती जाती तथा थानाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाता तो उक्त घटना घटित न होती। उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि हेड मोहर्रिर 10 ना0पु0 दिनेश राणा, कानि0 क्लर्क 352 नापु0 दिनेश सिंह, कानि 489 नापु0 सतीश कुमार व निगरानी पर नियुक्त कानि0 477 ना0पु0 दिपेन्द्र सिंह द्वारा इस प्रकार का कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता का द्योतक है।

निष्कर्ष – सम्पूर्ण जांच के दौरान लिये गये बयानात, गवाहन एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व वस्तुस्थिति का गहनता से परिशीलन के उपरान्त (1)–थानाध्यक्ष श्री खजान सिंह चौहान अधीनस्थों से अपने कर्तव्यों पालन कराने में शिथिल पाये गये । (2)– कानि0 क्लर्क 352 ना0पु0 दिनेश सिंह व कां0 489 ना0पु0 सतीश कुमार अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन न करने के लिए तथा (3) –हेड मोहर्रिर 10 ना0पु0 दिनेश राणा व कां0 477 नापु0 दिपेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त अजयपाल को अभिरक्षा से भाग जाने में लापरवाही बरतने के दोषी पाये गये।"

5.2 It has been contended by the respondents that the findings of the inquiry officer are based on sufficient evidence. After due consideration of the inquiry report by the disciplinary authority, show cause notice was issued to the petitioner for imposing minor penalty of censure to the petitioner. Thus, he was given reasonable opportunity to defend himself following the principles of natural justice. His reply to the show cause notice was duly considered by the disciplinary authority and minor punishment of censure entry was awarded to the petitioner. The appeal of the petitioner against the punishment order was also considered and the appellate authority rejected the same by passing a detailed order as per rules.

6. The petitioner has also filed rejoinder affidavit and the same averments have been reiterated and elaborated in it which were stated in the claim petition.

7. I have heard both the parties and perused the record.

8. Before the arguments of the parties are discussed, it would be appropriate to look at the rule position related to the minor punishment in Police Department. Relevant rules of the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991 (as applicable in the state of Uttarakhand) are given below:-

> ***"4. Punishment*** *(1)The following* ***punishments*** *may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed upon a* ***Police Officer****, namely:-*
>
> *(a) Major Penalties :-*
>
> *(i) Dismissal from service,*
>
> *(ii) Removal from service.*
>
> *(iii) Reduction in rank including reduction to a lower scale or to a lower stage in a time-scale,*
>
> ***(b) Minor Penalties :-***
>
> *(i) With-holding of promotion.*
>
> *(ii) Fine not exceeding one month's pay.*
>
> *(iii) With-holding of increment, including stoppage at an efficiency bar.*
>
> ***(iv) Censure.***
>
> *(2)……..*
>
> *(3)……..."*

> ***"5. Procedure for award of punishment****- (1) The cases in which major punishments enumerated in Clause (a) of sub-rule (1) of Rule 4 may be awarded*

shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in sub-rule (1) of Rule 14.

*(2)**The case in which minor punishments enumerated in Clause (b) of sub-rule (1) of Rule 4 may be awarded, shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in sub-rule (2) of Rule 14**.*

(3)……………………………."

***"14. Procedure for conducting departmental proceedings**- (1) Subject to the provisions contained in these Rules, the departmental proceedings in the cases referred to in sub-rule (1) of Rule 5 against the Police Officers may be conducted in accordance with the procedure laid down in Appendix I.*

*(2) **Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) punishments in cases referred to in sub-rule (2) of Rule 5 may be imposed after informing the Police Officer in writing of the action proposed to be taken against him and of the imputations of act or omission on which it is proposed to be taken and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal**.*

(3)………………………"

9. The above rule position makes it clear that in order to impose minor penalty, it is mandatory to inform the Police Officer in writing of the action proposed to be taken against him and of the imputations of act or omission on which it is proposed to be taken and to give him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposed minor penalty.

10. Learned counsel for the petitioner as well as learned A.P.O. have argued on the same lines which have been stated in paragraphs 4 and 5 of this order.

11.1 Learned counsel for the petitioner has argued that the petitioner has been falsely implicated. The petitioner was not present at the place of incident. The petitioner has not

committed any misconduct. Learned A.P.O. has refuted the argument and contended that the preliminary inquiry was conducted against the petitioner and allegations against him were found correct. The findings of the preliminary inquiry are based on the statements of persons (including the petitioner) who were present at the place of incident. Learned A.P.O. also stated that the perusal of inquiry report makes it clear that sufficient evidence were found against the petitioner to hold him guilty. While perusing the original record of inquiry by me, it was also found that in reply to the show cause notice, the petitioner has admitted his presence at the place of incident. However, the petitioner in his reply to the show cause notice has pointed out some contradiction in the statements of various witnesses. Here, it would be pertinent to mention that this Tribunal is making a judicial review and not sitting as appellate authority. **It is settled principle of law that in judicial review, re-appreciation of evidence as an appellate authority is not made. The adequacy or reliability of the evidence is not the matter which can be permitted to be argued before the Tribuna**l.

11.2 After hearing both the parties and going through the record and also the claim petition/written statement/rejoinder, I find that a preliminary enquiry was conducted in a fair and just manner. The petitioner participated in the preliminary enquiry. The enquiry officer has taken statements of all the relevant witnesses including the petitioner. The preliminary enquiry is based on statements and documents related to the allegations. On the basis of sufficient evidence, the enquiry officer has reached the conclusion that the petitioner was guilty. The petitioner was also provided required opportunity to defend

himself. After the preliminary inquiry, the petitioner was issued a show-cause notice by the disciplinary authority. The reply of the petitioner to the show cause notice was also duly examined and considered and after that the disciplinary authority has passed the order awarding minor punishment of censure entry to the petitioner. It is settled position of law that this Tribunal cannot interfere in the findings of the enquiry officer recorded after the conclusion of the enquiry unless it is based on the malafide or perversity. The perversity can only be said when there is no evidence and without evidence, the enquiry officer has come to the conclusion of the guilt of the delinquent official. In the case in hand, there is sufficient evidence to hold the petitioner guilty for misconduct as recorded by the enquiry officer and there is no perversity or malafide in appreciation of evidence by the inquiry officer. From the perusal of record, it is also revealed that the show cause notice dated 03.10.2013 was issued and in his reply to this notice, the petitioner could not demonstrate any illegality in the show cause notice or in the procedure for awarding punishment of the censure entry. It is well settled principle of law that judicial review is not akin to adjudication on merit by reappreciating of the evidence as an appellate authority. The Tribunal does not sit as a court of appeal as the scope of judicial review is limited to the process of making the decision and not against the decision itself. Power of judicial review is meant to ensure that the delinquent receives fair treatment. The Tribunal is concerned to determine that the enquiry was held by a competent officer, that relevant rules and the principles of natural justice are complied with and the findings or conclusions are based on some evidence. The authority entrusted to hold enquiry has jurisdiction, power and

authority to reach a finding of fact or conclusion. The Disciplinary Authority is the sole judge of facts. In case of disciplinary enquiry, the technical rules of evidence and the doctrine of “Proof beyond doubt” have no application. “Preponderance of probabilities” and some material on record would be enough to reach a conclusion whether or not the delinquent has committed a misconduct. Adequacy of evidence or reliability of evidence cannot be permitted to be convassed before the Tribunal.

11.3 In the case in hand, after careful examination of the whole process of awarding minor punishment of censure to the petitioner, I find that the minor punishment was awarded to the petitioner after an enquiry. The enquiry was based on evidence and there is no malafide and perversity. The petitioner was given reasonable opportunity to defend himself. There is no violation of any rule, law or principles of natural justice in the enquiry proceedings conducted against the petitioner.

12. Learned counsel for the petitioner has also argued that the criminal case was also instituted against the petitioner and both the departmental proceedings as well as criminal proceedings were based on similar and identical set of facts and, therefore, it was desirable to stay the departmental proceedings till the conclusion of the criminal case by the Court which was not done. It may be pertinent to note here that the general principle in service jurisprudence is that disciplinary and criminal proceedings can go on simultaneously and different conclusions can be reached in the two proceedings because the degree of proof required in the two proceedings is different. The settled legal position is that the disciplinary proceedings are desirable to be kept in abeyance only when it is established that

the non-stayal of the disciplinary proceedings shall not only prejudice the delinquent officer in criminal trial but the matter also involves a complicated question of law or fact. In the case in hand, neither in the claim petition nor at the time of argument, it has been contended that the matter involved a complicated question of law or fact and the disciplinary proceedings have caused prejudice to the petitioner in the criminal trial. Moreover, the petitioner has been awarded minor punishment of censure entry for negligence and lack of devotion in the performance of his duties. The petitioner who was present in the police station at the time of incident was found guilty for not keeping the key of lock up with him and the fact that the accused in custody was taken from lock-up to dining hall for food, the petitioner was punished for carelessness and indiscipline by the disciplinary authority. Thus, even if the facts of the incident were similar but the purpose of the disciplinary proceedings and criminal proceedings was entirely different. Under these circumstances, the argument of learned counsel for the petitioner that because of criminal proceedings were also initiated and, therefore, the departmental proceedings should have been stayed has no force and cannot be accepted. Learned counsel for the petitioner has referred the case-law **Captain A.Paul Anthony Vs. Bharat Gold Mines, AIR 1999 SC 1416**. I have gone through the case and find that the facts and circumstances in the case in hand are entirely different compared to the referred case law and the same is not applicable in the present case and the referred case law is of no help to the petitioner.

13. Learned counsel for the petitioner has also argued that according to Regulation 492 of the U.P. Police Regulations, when

the criminal trial is pending, the departmental proceedings cannot be initiated. The Regulation 492 reads as under:-

> *"492- Whenever a police officer has been judicially tried, the Superintendent (of police) must await the decision of the judicial appeal, if any, before deciding whether further departmental action is necessary*."

The perusal of Regulation 492 reveals that the Regulation applies when (i) the police officer has been tried for a criminal offence; and (ii) the criminal trial is over and the judicial appeal is pending. Under these circumstances, if departmental inquiry is considered to be initiated, the Superintendent of Police must await the decision of the judicial appeal. The facts in the case in hand are entirely different. The departmental inquiry was conducted and finalized before the judgment of the criminal trial. There is no judicial appeal pending and there is no situation of initiation of the departmental inquiry. The departmental inquiry is already over even before the judgment of the original criminal trial. Therefore, the Regulation 492 is not at all applicable in the case in hand and the argument of learned counsel regarding Regulation 492 is misconceived and is of no help to the petitioner.

14. Learned counsel for the petitioner has also filed the judgment of the Chief Judicial Magistrate, Pauri dated 17.02.2017 by which the petitioner has been acquitted as the charge against him under Section 217 and 223 of the IPC were not found proved. The departmental proceedings against the petitioner were independent of the criminal proceedings and the minor punishment of censure entry has been imposed upon the petitioner for a misconduct of negligence and carelessness in

performing of his duties as has been mentioned earlier in paragraph 12 of this order. Moreover, the petitioner in his claim petition has not made any pleadings or amended his pleadings later to make his acquittal as a ground to challenge the punishment/appellate order.

15. For the reasons stated above, there is no force and the claim petition is devoid of merit and the same is liable to be dismissed.

ORDER

The petition is hereby dismissed. No order as to costs.

D.K.KOTIA
VICE CHAIRMAN (A)

DATE: AUGUST 28, 2017
DEHRADUN

KNP